



NaMo 25 · #25YearsofSeva

44 मंत्रालय · मंत्रालय-दर-मंत्रालय

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

सुगम्य भारत से 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण तक

7 अक्टूबर 2001 → 7 अक्टूबर 2026 · 25 साल, ज़ीरो ब्रेक · 25YearsofSeva.com · संस्करण 88 · 7 अक्टूबर 2026
हर आँकड़ा तिथि सहित — पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर।



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सुगम्य भारत से 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण तक

- 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिव्यांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किए गए; 3 दिसम्बर 2015 से सुगम्य भारत अभियान चल रहा है।
- अगस्त 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला; 14 जनवरी 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण लागू है।
- 5 अप्रैल 2016 से स्टैंड-अप इंडिया अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण देती है।